ये पृथ्वी का स्वर्ग, यहां की माटी चन्दन है।
कभी तीज-त्यौहार कभी मेलों का मौसम आए,
जन-जीवन पत्थर के डर से भी रस-धार बहाए।
रात ढले चौपालों पर जब सांगी सांग सुनाए,
ढोलक, डफ, खड़ताल बजें, सारंगी रंग जमाए
लूर नृत्य या वृंदगान में,
आल्हा की रस भरी तान में,
रागनियों से भरा लोक-मानस का स्पंदन है।
हरियाणा की देवभूमि! तेरा अभिनन्दन है।

उदयभानु हंस

2 साल

सबका ख़्याल

हरियाणा एक - हरियाणवी एक

- परिकल्पना धीरा खंडेलवाल, समीर पाल सरो
- समन्वयक संवर्तक सिंह, राज पन्नू, अनीता दत्ता
- ले -आउट सुरेंद्र बांसल
- सज्जा गुरप्रीत सिंह
- चित्र विनय मलिक
- डिजिटल सपोर्ट विकास डांगी
- स्रोत सहयोग विनोद कुमार
- प्रूफ सुखविंदर कौर, सुनीता तथा गीता
- टाईपिंग पूजा, हेमा

निदेशक - सूचना ,जन संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्धारा प्रकाशित तथा संवाद सोसाइटी के माध्यम से मुद्रित (अक्तूबर - 2016)

अनुक्रम

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15
2. क्षतिग्रस्त फसलों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी 17
3. किसानों के हित में नई पहल 19
4. बागवानी फसलें-खुशहाली का प्रतीक 21
5. टेल तक पानी पहुंचाने की कटिबद्धता 23
6. सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प 25
7. पशुधन संवर्द्धन के नये प्रयास 27
8. दुग्ध उत्पादन में अग्रणी हरियाणा 29
9. डेरी विकास-खुशहाली का प्रतीक 31
10. सहकारी समितियां-किसानों के हित में 33
11. सहकारी चीनी मिलों को सहायता 35
12. अनाज मण्डियों में ऑनलाइन सुविधा 37
13. फसलों की खरीद के उचित प्रबन्ध 39
14. कैरोसिन मुक्त होगा राज्य 41
15. राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन में ऑनलाइन सुविधाएं शुरू 43
16. स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत 45
17. पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हरियाणा 47
18. विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं 49
19. शिक्षित पंचायतें- समाज की रीढ़ 51
20. प्राथमिक शिक्षा-भविष्य का आधार 55
21. स्कूली शिक्षा-मज़बूत नींव 57
22. नैतिक मूल्यों व चरित्र निर्माण पर आधारित उच्चतर शिक्षा 59
23. तकनीकी शिक्षा -स्वर्णिम भविष्य का प्रतीक 61
24. औद्योगिक प्रशिक्षण से युवाओं का कौशल विकास 65
25. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति 67
26. निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु प्रभावी कदम 71
27. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार 73
28. औद्योगिक विकास-मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार 77
29. निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हरियाणा 81
30. हरियाणा विदेशी निवेशकों की पहली पंसद 85
31. खनन के ठेकों में पारदर्शिता 87
32. सड़कों का विस्तार-विकास का आधार 89
33. पुलों का निर्माण-यातायात आसान 91
34. रेल यातायात को नई दिशा 93
35. स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति-सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 95
36. कराधान के क्षेत्र में ई-सेवाओं की शुरुआत 97
37. सस्ती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं 99
38. प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज 105
39. ई.एस.आई. अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण 107
40. आयुर्वेद चिकित्सा को प्राथमिकता 109
41. शहरों का कायाकल्प 111
42. मैट्रो से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर 115
43. आधुनिक तथा सुगम परिवहन सेवाएं 117
44. हवाई अड्डों का अपग्रेडेशन 119
45. सामाजिक सुरक्षा की नई पहल 121
46. नागरिकों की सुरक्षा हेतु योजनाएं 123
47. बेटी को सलाम-राष्ट्र के नाम 125
48. सशक्त महिला-सशक्त समाज 127
49. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा 131
50. गांवों में भी मिलेंगी भरपूर खेल सुविधाएं 135
51. पर्यटन को बढ़ावा 139
52. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु उचित कदम 141
53. वीरों एवं शहीदों का बढ़ाया सम्मान 143
54. कर्मचारी कल्याण 145
55. सबके सिर पर छत 147
56. हर घर हरियाली 149
57. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता 151
58. श्रमिकों का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान 153
59. रोज़गार के नये अवसर 155
60. प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था 157
61. हरियाणा की अर्थव्यवस्था देश में अग्रणी 161

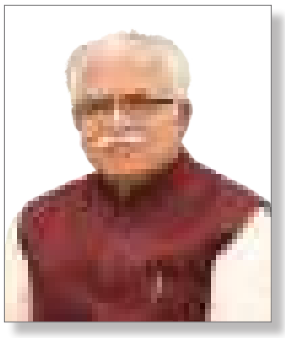

विकास की बुलंदियां छूता हरियाणा

मेरे प्रिय हरियाणावासियों,

मैं, आप सब को बधाई देना चाहता हूँ कि 26 अक्तूबर, 2016 को हमारी सरकार आप सबके सहयोग से अपने दो वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर रही है। यह भी हर्ष का विषय है कि आगामी 1 नवम्बर, 2016 को हरियाणा राज्य अपने गठन के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर रहा है तथा 31 अक्तूबर, 2017 तक की अवधि को स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह वर्ष हरियाणा के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष है। इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष का शुभारम्भ एक उत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। हमने इस वर्ष गीता जयन्ती समारोह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें भगवद्गीता के शाश्वत संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जायेगा।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश का चहुँमुखी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और दो साल के कार्यकाल में हर वर्ग का ख्याल रखा है। हरियाणा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर रखना हमारा परम कर्त्तव्य है। इसी सोच के मद्देनज़र सरकार ने गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से गौ संरक्षण अधिनियम बनाया। विलुप्त सरस्वती नदी के पुनरूत्थान के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने सुशासन एवं पारदर्शी सरकार देने के अपने वायदे को 'डिजिटल हरियाणा' तथा नौकरियों में मैरिट को आधार बनाकर हकीकत में बदला है। आज हरियाणा 'ई-सेवाओं' का पर्याय बन गया है, जिससे जनता के कार्य समयबद्ध और निर्बाध पूरे हो रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रियो ओलम्पिक, 2016 में साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर तथा पैरालम्पिक में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

'दो साल-सबका ख्याल' नामक इस पुस्तिका में जन-कल्याणकारी नीतियों एवं कुछ प्रमुख उपलब्धियों का संकलन किया गया है, ताकि आप सब इन कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठा सकें। आइए, इस पुनीत पर्व पर हम सब मिलकर इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में हरियाणा को स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प लें।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

मंत्री परिषद्

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री
चौथी मंजिल, सचिवालय

''बच्चे हमारा भविष्य हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि भावी पीढ़ी को शाब्दिक ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाए ताकि समाज को संस्कारवान नागरिक मिल सकें। इसी उद्देश्य के लिए बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य की गई है''

राम बिलास शर्मा
शिक्षा मंत्री
कमरा नं. 32/8, सचिवालय

''पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी अर्थ-चिंतन के भाव से प्रेरित होकर कार्य कर रही है। हमने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। हमें अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके विकास के अभीष्ट लक्ष्य को हासिल करना है''

कैप्टन अभिमन्यु
वित्त मंत्री
कमरा नं. 40/5, सचिवालय

''किसान हमारा अन्नदाता है लेकिन जब उसका पेट भरा होगा तभी वह औरों का पेट भर पाएगा। इसलिए किसान बेहतरी के लिए कार्य करना हमारा पहला उत्तरदायित्व है। यह काम समय पर अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक और आधुनिक कृषि उपकरण मुहैया करवाकर ही किया जा सकता है। सरकार न केवल इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है बल्कि उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना भी हमारी प्राथमिकता है''

ओम प्रकाश धनखड़
कृषि मंत्री
कमरा नं. 34/8, सचिवालय

''योग एवं व्यायाम आरोग्य जीवन का आधार है, इससे स्वस्थ चिंतन को बल मिलता है। इसके लिए प्रदेशभर में 'व्यायाम एवं योगशालाओं' की स्थापना तथा आयुष को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के तौर पर विकसित किया जा रहा है''

अनिल विज
स्वास्थ्य मंत्री
कमरा नं. 49/8, सचिवालय

''किसी भी राज्य के समूचे विकास के लिये सुदृढ़ आधारभूत संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने आते ही राज्य की लगभग सभी सड़कों का सुधार किया और कई नई सड़कें बनवाईं हम अगले साल तक राज्य की सड़कों की कायापलट कर देंगे। इसके अलावा, हवाई यातायात के बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। हमारी सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली की बदौलत अब प्रदेश की जनता को 'बदलता हरियाणा-बढ़ता हरियाणा' देखने को मिल रहा है''

नरबीर सिंह
लोक निर्माण मंत्री
कमरा नं. 39/8, सचिवालय

''हरियाणा में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान तथा महिला पुलिस थानों की स्थापना से जाहिर होता है कि हमारी सरकार महिलाओं और बेटियों के सम्मान के प्रति बेहद संजीदा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत महिलाओं को गैस कनैक्शन मुफ्त उपलब्ध कराये जा रहे हैं''

कविता जैन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
कमरा नं. 43-ए/8, सचिवालय

''प्रदेश सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के दर्शन पर चलते हुए पिछले दो वर्षों में समाज के हर तबके की बेहतरी के लिए काम किया है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास रहने को अपना एक घर हो। हम वर्ष 2022 तक हर बेघर को घर मुहैया करवाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2019 तक दो लाख परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है''

कृष्ण लाल पंवार
परिवहन मंत्री
कमरा नं0 24/8, सचिवालय

''गुरुग्राम में आयोजित 'ग्लोबल सम्मिट' उद्योग जगत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसके फलस्वरूप निवेशकों ने प्रदेश में निवेश करने को अहमियत दी है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 'मेक इन हरियाणा' कार्यक्रम चलाया है। हरियाणा अब निवेशकों की पहली पंसद बन गया है''

विपुल गोयल
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
कमरा नं. 42/6, सचिवालय

राज्य मंत्री

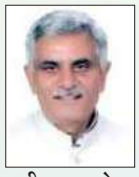

''हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य 'सबका साथ-सबका विकास' है। हमारा प्रदेश पूरे देश में खेती के क्षेत्र में और दूध उत्पादकता के लिये प्रसिद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों, दूध उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों के लिये अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है''

मनीष कुमार ग्रोवर
सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

''प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई है, जिसने सही मायने में पिछड़े और उपेक्षित वर्गों की सुध ली है। इन वर्गों में एक नई आशा और उत्साह का संचार किया है। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की समस्याओं का निराकरण करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है''

कृष्ण कुमार बेदी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
कमरा नं. 40/5, सचिवालय

''स्वच्छ राशन की सहज आपूर्ति और उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए विभाग को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश को कैरोसिन मुक्त बनाकर लोगों को एल.पी.जी. गैस उपलब्ध करवायी जा रही है''

कर्ण देव काम्बोज
खाद्य एवं आपूर्ति, स्वतंत्र प्रभार
कमरा नं. 47/8, सचिवालय

''योग्य को रोज़गार और बेरोज़गार को भत्ता देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके पहले चरण में स्नातकोत्तर बेरोज़गार युवकों के लिए 100 कार्य घंटों पर 9000 रुपये 'मासिक भत्ता योजना' शीघ्र शुरू की जाएगी''

नायब सिंह
श्रम एवं रोजगार मंत्री
कमरा नं. 44बी/6, सचिवालय

''राज्य में लोगों को स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मलिन व बी.पी.एल. बस्तियों में पानी के कनैक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ 10 हजार या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों में सीवरेज प्रणाली की सुविधा भी प्रदान की जाएगी''

डॉ. बनवारी लाल
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री
कमरा नं. 29, सचिवालय

मुख्य संसदीय सचिव

श्याम सिंह
कारागार, मुख्यमंत्री से सम्बद्ध
कमरा नं. 30/9, सचिवालय

बख्शीश सिंह विर्क
विकास एवं पंचायत, कृषि मंत्री से सम्बद्ध
कमरा नं. 40/6, सचिवालय

सीमा त्रिखा
पर्यटन तथा सत्कार, शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध
कमरा नं. 50/8, सचिवालय

डॉ. कमल गुप्ता
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मंत्री से सम्बद्ध
कमरा नं. 26/8, सचिवालय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के हितार्थ 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों में धान, बाजरा, मक्का व कपास तथा रबी फसलों में गेहूँ, जौं, सरसों व चना को शामिल किया।
- खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर अधिकतम 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत होगी।
- कपास की फसल पर अन्य खरीफ फसलों के समान 2 प्रतिशत ही अधिकतम प्रीमियम होगा तथा अतिरिक्त 3 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- इस योजना के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इस योजना के अन्तर्गत 6.92 लाख किसानों की 11.40 लाख हैक्टेयर भूमि को कवर किया गया।

किसान हितैषी 'फसल बीमा योजना' लागू

क्षतिग्रस्त फसलों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कुल 2413.37 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की, जिसमें पिछली सरकार की 269 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी शामिल है।
- प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ तक की।
- कम से कम नुकसान होने पर भी छोटे से छोटे हिस्सेदार को भी न्यूनतम 500 रुपये मुआवजा।
- जिन क्षेत्रों में फसलें 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई, उन क्षेत्रों में एक वर्ष के लिए किसानों के कृषि के बिल शत-प्रतिशत माफ।
- जिन क्षेत्रों में फसलें 25 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक खराब हुई, उन क्षेत्रों में किसानों के ट्यूबवैल के बिल 50 प्रतिशत माफ।

किसान हित में किया पिछली सरकार की बकाया राशि का भुगतान

2 साल
सबका ख़्याल

MANOHAR LAL
NITIN GADKA

किसानों के हित में नई पहल

- प्रदेश के इतिहास में पहली बार मूंग की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।
- प्रदेश में पहली बार बाजरे की सरकारी खरीद सुनिश्चित करवाई गई।
- प्रदेश के सभी किसानों को 'सॉयल हैल्थ कार्ड' योजना के अन्तर्गत मृदा नमूने के परीक्षण कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- इस योजना के तहत लगभग 757 लाख मृदा नमूनें एकत्रित किए गये, जिनमें से लगभग 334 लाख कार्ड परीक्षण उपरान्त वितरित।
- प्रदेश को धान उत्पादकता के लिए 'कृषि कर्मण' पुरस्कार मिला।
- हरियाणा केन्द्रीय पूल में योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- पर्यावरण एवं मृदा स्वास्थ्य के लिए जैव उर्वरकों पर लागू 5 प्रतिशत वैट समाप्त।
- करनाल व सिरसा में दो कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है।

पहली बार मूंग की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर

2 साल
सबका ख़्याल

बागवानी फसलें-खुशहाली का प्रतीक

- करनाल के गांव अंजनथली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
- इस विश्वविद्यालय के तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र जिला झज्जर, अम्बाला व जीन्द में स्थापित किए जाएंगे।
- हरियाणा को बागवानी क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के लिए "Best Horticulture State Award" से नवाजा गया।
- बागवानी से सम्बन्धित उत्पादों के लिए 'हरियाणा फ्रैश' नामक ब्रांड शुरू।
- शामगढ़ (करनाल) में 425 करोड़ रुपये की लागत से उद्यान बायो तकनीकी केन्द्र तथा लाडवा (कुरुक्षेत्र) में 9.10 करोड़ रुपये की लागत से उपोषण फल केन्द्र बनाए गए।
- किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान देकर 308 नए तालाब बनाए गए।
- 'एकीकृत उद्यान विकास मिशन' के अन्तर्गत बागवानी फसलों पर 98.87 करोड़ रुपये का अनुदान।
- स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अन्तर्गत शिवालिक विकास हेतु 2.92 करोड़ रुपये तथा फार्म व विपणन हेतु 93.02 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- कृषि व्यवसाय संघ व नाबार्ड ने 13 किसान संगठनों के लिए एक एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए नाबार्ड द्वारा 4.2 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

बागवानी फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा

2 साल
सबका ख़्याल

टेल तक पानी पहुंचाने की कटिबद्धता

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से 39 वर्ष बाद पहली बार दक्षिण हरियाणा के हसनपुर एवं दनचौली माइनरों में पहुंचा पानी।
- दक्षिण हरियाणा के नलवाटी क्षेत्र के 12 गांवों में 35 वर्ष बाद तालाब एवं सिचांई के लिए पहुंचा पानी।
- मैसानी बैराज को 50 वर्ष बाद भरा गया जिससे आस-पास के क्षेत्र में भू-जल 10 से 20 फुट बढ़ा।
- मेवात क्षेत्र में भू-जल सरंक्षण, पीने के पानी व सिंचाई के लिए कोटला झील का लगभग 81 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णोद्धार एवं विकास कार्य प्रगति पर। इससे लगभग 27,000 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।
- दक्षिणी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना तैयार, जिससे उपलब्ध होगा लगभग 5000 क्यूसिक अतिरिक्त पानी।
- बाढ़ के पानी से सिंचाई और भू-जल संरक्षण के लिए 6.41 करोड़ रुपये की लागत से 390 इंजेक्शन कुएं तैयार करने का कार्य प्रगति पर।
- 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत 47,201 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अधीन लाया गया।
- जे.एल.एन.नहर प्रणाली के पुर्ननिर्माण की एक मुख्य परियोजना 143 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत, जिसका कार्य वर्ष 2018 तक होगा पूरा।
- निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग में लाई जा रही सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से 565 जलमार्गों के पुर्नवास की परियोजना को मंजूरी।
- नहरों की मरम्मत और सफाई पर 135 करोड़ रुपये खर्च किये गए।
- पेटवाड़, हिसार, परिथला, पहाड़पुर माईनर, खनौरी माईनर, जखौली, टोहाना, नई उरलाना माईनर, जहांगीरपुर माईनर, लोहारू शाखा आदि के पुनर्वास का कार्य 150 करोड़ रुपये की लागत से शुरू।
- बाढ़ नियंत्रण की 210 योजनाएं शुरू, जिनकी लागत 275.32 करोड़ रुपये, जिनमें से 141.21 करोड़ रुपये की लागत की 159 परियोजनाओं का कार्य पूरा और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।

39 वर्ष बाद पहली बार दक्षिण हरियाणा के हसनपुर एवं दनचौली माईनरों में पहुंचा पानी

2 साल
सबका ख़्याल

सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प

- राज्य सरकार सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करने व रावी- ब्यास का हरियाणा के वैध हिस्से का पानी लेने के लिए कृत-संकल्प है। इस सम्बन्ध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तथा हरियाणा विधान सभा से राज्य के वैध हितों के विरुद्ध पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम के विरोध में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करवाया गया।
- हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को फरवरी, 2015 में पत्र लिखकर आग्रह किया कि सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया/अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति संदर्द की निगरानी करे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह करे।
- माननीय मुख्यमंत्री ने गत वर्ष आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक में इस मुद्दे को उठाया था तथा भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह करे।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर 29 फरवरी, 2016 को सुनवाई की। इसके बाद इसकी निरन्तर सुनवाई 12 मई, 2016 तक हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है।

2 साल
सबका ख़्याल

पशुधन संवर्द्धन के नये प्रयास

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु एक सशक्त कानून ''हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौ-संवर्धन अधिनियम-2015'' लागू।
- इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराध गैर-जमानती होंगे, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास व एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान।
- अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद एवं प्रयोग किये जाने वाले वाहन को जब्त करने के अतिरिक्त 70 हजार रुपये तक का जुर्माना।
- जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक साल तक की अतिरिक्त कैद का प्रावधान।
- बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर गौ अभ्यारण्यों की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत हिसार, यमुनानगर तथा पानीपत जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू।
- देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए ''गोकुल ग्राम परियोजना'' के अन्तर्गत हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 'एकीकृत पशुधन बीमा योजना' का कार्यान्वयन, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुओं की असामयिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- पशुपालकों को पांच बड़े पशु के लिए मात्र 100 रुपये तथा 50 छोटे पशु के लिए मात्र 25 रुपये तीन वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रीमियम की राशि अदा करनी होती है।
- हिसार में इन्डो इज़राईली उत्कृष्टता केन्द्र को स्थापित करने के लिये हरियाणा सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय विकास सहकारिता एजेन्सी, विदेश मन्त्रालय मामले, इज़राईल (MASHAV) के बीच एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर।

राज्य में ''हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौ-संवर्धन अधिनियम लागू

2 साल
सबका ख़्याल

दुग्ध उत्पादन में अग्रणी हरियाणा

- हरियाणा देश का पहला राज्य बना, जहां देशी गाय का पास्चुरीकृत ए-2 दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध।
- हरियाणा राज्य प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 835 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।
- कुरुक्षेत्र स्थित वीटा मिल्क प्लांट देशी गायों के दूध के प्रसंस्करण के लिए समर्पित।
- गायों की देशी नस्लों के संरक्षण एवं विकास तथा राज्य में गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए देशी गायों की 'मिनी डेरी योजना' शुरू, जिसके अन्तर्गत 3 से 5 गायों की डेरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- हरियाणा गौ सेवा आयोग को 9. 20 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए तथा 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- हरयाना, साहीवाल व गिर नस्लों के सुधार के लिए 'राष्ट्रीय गौ-भैंस प्रजनन व डेरी विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत 24 करोड़ 2 लाख रुपये स्वीकृत।
- हरयाना और साहीवाल नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- अधिक दूध देने वाली मुर्राह भैंस के पालकों को प्रतिदिन दूध उत्पादन के आधार पर 10,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- राज्य के इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रौल पम्पों पर वीटा मिल्क बूथ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

देश का पहला राज्य जहां देसी गाय का पास्चुरीकृत ए-2 दूध वीटा बूथों पर उपलब्ध

2 साल
सबका ख़्याल

Dairy

डेरी विकास-खुशहाली का प्रतीक

- राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 नवम्बर, 2016 से 'स्वर्ण जयंती सुरभि बाल दुग्ध' योजना शुरू, जिसके तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड-डे मील के अन्तर्गत 200 मिलीलीटर प्रति बच्चा के हिसाब से दूध दिया जाएगा।
- 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दिया जाने वाला अनुदान 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया।
- 'कन्यादान योजना' के तहत दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी बेटी की शादी पर 1100 रुपये की शगुन राशि।
- 'छात्रवृत्ति योजना' के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें क्रमशः एकमुश्त 2100 रुपये एवं 5100 रुपये की राशि देने का प्रावधान।
- 'दुर्घटना बीमा योजना' के तहत प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 लाख रुपये तक की योजना लागू।

सरकारी स्कूलों में 'स्वर्ण जयंती सुरभि बाल दुग्ध' योजना शुरू

सहकारी समितियां-किसानों के हित में

- समय पर अदायगी करने वाले किसानों को दिया जा रहा है बिना ब्याज सहकारी ऋण।
- प्राकृतिक प्रकोप से 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों के नुकसान वाले क्षेत्रों के सभी किसानों के रबी-2014 के फसली ऋणों को तीन वर्ष के लिए मध्यम अवधि ऋणों में बदला।
- 'सामाजिक सुरक्षा योजना' के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 3.60 लाख लाभार्थियों को पेंशन व भत्तों का वितरण किया जा रहा है।
- पंचायती चुनावों के लिए लागू नई शर्तों के परिणामस्वरूप सहकारी बैंकों को लगभग 213.07 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों की वसूली हुई।
- हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- किसानों को खरीफ-2015 के दौरान 4580.84 करोड़ रुपये तथा रबी 2015-16 के दौरान 4885 करोड़ रुपये के फसली ऋण उपलब्ध करवाए।

सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

2 साल
सबका ख़्याल

MASSEY FERGUSON 241 DI

सहकारी चीनी मिलों को सहायता

- शाहबाद सहकारी चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार।
- करनाल सहकारी चीनी मिल का गन्ना विकास में द्वितीय पुरस्कार हेतु चयन।
- 'सघन गन्ना विकास योजना' के तहत सभी दस सहकारी चीनी मिलों के लिए 25.22 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।
- किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को 646 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया।
- पानीपत की वर्तमान चीनी मिल का नये स्थान गांव डाहर में होगा स्थानान्तरण।

शाहबाद सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में प्रथम पुरस्कार

2 साल सबका ख़्याल

अनाज मण्डियों में ऑनलाइन सुविधा

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश में पहली बार व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की।
- 'राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल' कार्यक्रम के तहत देश के 8 राज्यों में हरियाणा भी शामिल।
- प्रदेश की 37 अनाज मण्डियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ दिया गया है तथा 31 मार्च, 2017 तक प्रदेश की सभी मण्डियों को इस प्लेटफार्म से जोड़ दिया जायेगा।
- 'ई-मण्डी' के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को देश के किसी भी हिस्से में ऑनलाइन बेच सकेंगे।
- मार्किट फीस की चोरी रोकने के लिए मंडियों में आवक का रिकॉर्ड रखने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली शुरू।
- पूरे प्रदेश में व्यापार करने के लिए एकल लाइसेंस देने तथा मार्किट फीस भी एक ही जगह पर जमा करने की सुविधा।
- कपास की खरीद पर मार्किट फीस 2 प्रतिशत से घटाकर 0.8 प्रतिशत की।
- 'कृषक उपहार' योजना के तहत मंडियों में 5000 रुपये या इससे अधिक की फसलें लाने वाले किसानों को 12 करोड़ रुपये के ईनाम/उपहार देने का प्रावधान।

किसानों को 'ई-मण्डी' के माध्यम से ऑनलाइन बेचने की सुविधा

2 साल सबका ख़्याल

फसलों की खरीद के उचित प्रबन्ध

- भौरसैन्दा (कुरुक्षेत्र), खरखौदा (सोनीपत) तथा तिगांव (फरीदाबाद) में क्रमशः 26,380, 42,200 व 21,098 मीट्रिक टन कुल क्षमता 89,678 मीट्रिक टन के गोदामों के निर्माण हेतु तीन परियोजनाएं स्वीकृत, जिसमें से तिगांव जिला फरीदाबाद के गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण।
- रबी सीज़न 2016-17 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रुपये, जौं का 1225 रुपये, चने का 3425 रुपये (75 रुपये बोनस), मसूर का 3325 रुपये, सरसों का 3350 रुपये तथा सूरजमुखी का 3300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपये से बढ़ाकर 1470 रुपये प्रति क्विंटल किया तथा ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये से बढ़ाकर 1510 रुपये प्रति क्विंटल किया।
- राज्य सरकार द्वारा 'बिल्ड ऑन ऑपरेट' मॉडल पर आधारित उचित मूल्य दुकान के सिस्टम इंटीग्रेटर (निजी एजेंसी) से अनुबंध किया जा चुका है।
- चमक रहित गेहूँ के दानों पर 11 जिलों में वैल्यू कट में छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80-95 प्रतिशत तक की।

पहली अप्रैल, 2017 तक समस्त राज्य होगा कैरोसिन मुक्त

2 साल
सबका ख़्याल

महिलाओं को
मिला सम्मान
स्वच्छ ईंधन
बेहतर जीवन

कैरोसिन मुक्त होगा राज्य

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिये 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है, अब तक 1,54,856 परिवारों को गैस कनैक्शन दिए।
- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रयासों से प्रदेश को कैरोसिन मुक्त बनाने की योजना के अन्तर्गत 8 जिलों नामतः अम्बाला, गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकूला और यमुनानगर को कैरोसिन मुक्त बनाया तथा पहली अप्रैल, 2017 तक समस्त राज्य कैरोसिन मुक्त होगा।
- राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई.पी.डी.एस. पोर्टल की शुरुआत, जिसके तहत सभी कार्यों का संचालन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा।
- पहली नवम्बर, 2016 से राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को बिक्री यंत्र के माध्यम से वितरण शुरू हो जाएगा।

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनैक्शन उपलब्ध

2 साल
सबका ख़्याल

CM WINDOW
मुख्यमन्त्री समस्या निवारण पटल
आपकी समस्याओं का निदान
स्वागत हरियाणा
यहाँ पर मुख्यमन्त्री महोदय को समस्या निवारण के लिए दिए जाने वाले
जिला मुख्यालय: पंचकूला
Haryana Police
हरसमय
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
CM WINDOW

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन में ऑनलाइन सुविधाएं शुरू

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया।
- सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में वर्ष 2015 से ई-दिशा के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू।
- प्रदेश में पहली बार व्हाट्सअप जैसे सामाजिक मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल पानी के बहाव की निगरानी हेतु किया गया।
- फरवरी, 2016 में आंदोलन के दौरान ग्रामीण ईलाकों में सम्पत्ति के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान करने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।
- प्रदेश में मई, 2015 से ई-स्टैम्प प्रणाली योजना लागू।
- प्रत्येक मास की 12 व 26 तारीख (कार्य दिवस) इंतकाल शून्य करने के लिए निर्धारित।
- एन.आई.सी. द्वारा राजस्व विभाग के लिए 11 सेवाएं विकसित की गईं।
- राज्य सरकार में 10 नए उप मण्डल, 10 नई तहसीलें, तीन नई उप तहसीलें और 14 नए ब्लाक बनाने का निर्णय।

चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाया गया

स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत

- 'स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत' अभियान के अन्तर्गत राज्य को 2019 तक पूर्णतया स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निधार्रित।
- वर्ष 2017 तक प्रदेश के सभी पात्र परिवारों के लिए ग्रामीण व्यक्तिगत शौचालय निर्मित करने का लक्ष्य, जिसके तहत शौचालय बनाने के लिए वित्तीय सहायता 12,000 रुपये की।
- प्रत्येक माह खण्ड व जिला स्तर पर सबसे अच्छी साफ-सुथरी व खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का प्रावधान।
- सभी ग्राम पंचायतों में ठोस व तरल कूड़ा कचरा प्रबन्धन की सुविधा देने के लिए कार्य योजना तैयार।
- राज्य सरकार द्वारा 'स्वच्छ शहरी पुरस्कार योजना' शुरू, जिसके तहत प्रत्येक मास सबसे अच्छी साफ-सुथरी नगरपालिका के लिए 2 लाख रुपये तथा नगर समिति के वार्डों के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार निर्धारित।
- राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए 10,000 रुपये वहन किए जाएंगे।
- राज्य में 15,399 व्यक्तिगत घरेलू सार्वजनिक शौचालयों के लिए 4393 टॉयलेट सीट्स की पहचान की गई, जिनमें से 1515 शौचालयों का कार्य पूर्ण।
- जिले में साफ-सुथरे, अच्छे रख-रखाव वाले शौचालयों को 10,000 रुपये पुरस्कार देने का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय के लिए लाभान्वितों से 1,01,311 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा 56,603 शौचालयों का कार्य प्रगति पर।
- प्रदेश में कुल 2016 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया।

सभी पात्र परिवारों के लिए ग्रामीण व्यक्तिगत शौचालय निर्मित करने का लक्ष्य

2 साल सबका ख़्याल

ग्राम सचिवालय

पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हरियाणा

- ई-सेवाओं से युक्त 'ग्राम सचिवालय' की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू, जिसके तहत सभी आवश्यक सुविधाओं की एक ही परिसर में व्यवस्था होगी।
- वर्ष 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का प्रस्ताव, जिसमें 900 ग्राम सचिवालय स्थापित किये गये।
- सभी पंचायतों से सीधा सम्पर्क बनाने के लिए ई-पंचायत संवाद कार्यक्रम का जिला रोहतक से शुभारंभ।
- ई-मेल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं व हिदायतों की जानकारी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जाएगी।
- योजनाबद्ध विकास के लिए 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव के लिए 1461 करोड़ रुपये की लागत से 'स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास' योजना शुरू।
- 'स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण विकास निधि' के तहत सभी पंचायतों को पहली बार हर वर्ष जनसंख्या के आधार पर एक सुनिश्चित धन राशि विकास कार्यों के लिए दी जाएगी।
- ग्रामीण विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया जायेगा।

ई-पंचायत संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं

- 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम' योजना के तहत ज़िला पलवल तथा फरीदाबाद के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 12 गांवों को 10 लाख रुपये प्रति गांव दिए गए।
- 'सांसद आदर्श ग्राम' योजना के तहत प्रदेश के सभी सांसदों ने 15 गांव गोद लिये।
- 'विधायक आदर्श ग्राम' योजना के तहत 58 विधायकों द्वारा गांव गोद लिये गये।
- 'स्व प्रेरित आदर्श ग्राम' योजना के तहत 134 गांवों का चयन किया गया।
- माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदेश के गोद लिये हुए पांच गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजना के तहत गुड़गांव जिले के अलीपुर, दौला, हरचन्दपुर व ताजनगर तथा मेवात जिले का रोजकामेव गांवों को शामिल किया।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत राज्य के अम्बाला, फतेहाबाद, जीन्द, करनाल, रेवाड़ी एवं झज्जर जिलों में 6 क्लस्टरों नामतः बराड़ा, समैन, उचाना खुर्द, बाला, कौसली तथा बादली का चयन किया गया तथा प्रत्येक कलस्टर के लिए 35 लाख रुपये की राशि आवंटित।

'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम' योजना के तहत 10 लाख रुपये प्रति गांव दिए गए

2 साल सबका ख़्याल

विकसित हरियाणा की ठोस दलील पंचायतों का नव पचरील

साक्षर एवं सशक्त पंचायतें

"सशक्त ग्रामीण व्यवस्था का मूल आधार है शिक्षित पंचायतें। यदि गांव का नुमाईंदा साक्षर होगा, तभी उस गांव का सही विकास सुनिश्चित होगा। विकास के साथ ही सामाजिक व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन स्पष्ट नजर आयेंगे"।

मनोहर लाल

सोनीपत

रोहतक

शिक्षित पंचायतें- समाज की रीढ़

- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, जिसका उद्देश्य चुने जाने वाले प्रतिनिधि साफ छवि, कायदे कानून को मानने वाले और पढ़े-लिखे हों।
- साक्षर एवं सशक्त पंचायती व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों के विरुद्ध 42 प्रतिशत महिलाएं व अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि चुने गए।
- पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए सदस्यों की औसत आयु 34 साल होने से पंचायती राज संस्थाओं को युवा एवं गतिशील नेतृत्व मिला है।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में 84.4 प्रतिशत मतदान हुआ।
- साक्षर एवं सशक्त पंचायती व्यवस्था के लिए पंचायती राज संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि का मैट्रिक होना अनिवार्य।
- अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति महिला पंच का पांचवी पास होना अनिवार्य।
- अपराधिक प्रवृत्ति वाले, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं, बिजली बिल व सहकारी संस्थानों के बकायों का नियमित भुगतान न करने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी।
- 'स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण विकास योजना' के तहत 82 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था, जिसमें से 18 करोड़ रुपये की राशि जारी।

इस बार पंचायती राज संस्थाओं को युवा एवं गतिशील नेतृत्व मिला

2 साल
सबका ख़्याल

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशव्यापी 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान की शुरुआत बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू (मध्य प्रदेश) से की।
- प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर ''गर्वित-ग्रामीण विकास तरुण'' नामक नई मार्गदर्शक योजना शुरू।
- जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य का मानदेय क्रमशः 10,000 रुपये, 7500 रुपये व 3000 रुपये मासिक करने का निर्णय।
- पंचायत समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य का मानदेय क्रमशः 7500 रुपये, 3500 रुपये तथा 1600 रुपये मासिक करने का निर्णय।
- सरपंच तथा पंच का मानदेय क्रमशः 3000 रुपये तथा 1000 रुपये मासिक।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की पांच पंचायतों को 'पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार' तथा करनाल जिले के निसिंग ब्लॉक की ग्राम पंचायत 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा' पुरस्कार से सम्मानित।
- प्रत्येक गांव में योग के लिए दो एकड़ पंचायत भूमि पर व्यायामशालाएँ स्थापित की जाएंगी, जिसके लिये 600 से अधिक गांवों में उपयुक्त भूमि की पहचान की जा चुकी है।

पहली बार पढ़ी-लिखी पंचायतें

CALLIGRAPHY

प्राथमिक शिक्षा–भविष्य का आधार

- अध्यापकों के लिए नई पारदर्शी एवं निष्पक्ष ऑनलाइन 'स्थानांतरण नीति' बनाई, जिसके तहत 92 प्रतिशत से अधिक अध्यापक अपनी मनचाही जगह पर हुए नियुक्त।
- स्कूली पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक, स्वच्छता अभियान, योग व सड़क सुरक्षा से संबन्धित विषय शामिल।
- प्रदेश के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय बनाये गये।
- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 3222 प्राथमिक स्कूलों में एक महत्वाकांक्षी पहल Learner Enhancement Programme शुरू, जिसके तहत 18 हजार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
- विद्यार्थियों के अध्ययन के अंतर को पाटने के लिए 3200 प्राथमिक पाठशालाओं में रैमेडियल टीचिंग शुरू।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र देने की योजना शुरू।

स्कूली पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक, स्वच्छता अभियान, योग व सड़क सुरक्षा से संबन्धित विषय शामिल

2 साल
सबका ख़्याल

दैनिक जाग

स्कूली शिक्षा-मज़बूत नींव

- देश के इतिहास में पहली बार शिक्षा शास्त्रियों, अध्यापकों, बुद्धिजीवियों, गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों, गैर-सरकारी संगठनों व आम जनता से सुझाव मांगकर और गहन विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति-2015 बनाई जा रही है।
- नई शिक्षा नीति-2015 के लिए पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में हरियाणा की 6072 ग्राम पंचायतों, 126 खण्डों, 78 शहरी स्थानीय निकायों एवं 21 जिलों से सुझाव प्राप्त हुए।
- स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने में तेजी, ताकि 'मेक इन हरियाणा-मेक इन इण्डिया' अभियान को गति मिल सके।
- दसवीं कक्षा में 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 500 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना। वर्ष 2016-17 के बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पहली से 12वीं कक्षा तक मासिक परीक्षाएं शुरू, जिसकी समीक्षा ऑनलाइन की जाती है।
- अध्यापकों में स्व-अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक डायरी की अनिवार्यता।
- कक्षा नौंवीं से 12वीं तक समैस्टर सिस्टम समाप्त।

दसवीं कक्षा में 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप

नैतिक मूल्यों व चरित्र निर्माण पर आधारित उच्चतर शिक्षा

- प्रदेश में पांच नए राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा 22 नए राजकीय महाविद्यालय, 33 नये स्वःवित्त पोषित डिग्री कॉलेज तथा चार स्वः वित्त पोषित लॉ कॉलेज खोलने की मंजूरी।
- सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ई-पेंशन योजना शुरू।
- प्रदेश की पहली एनसीसी. अकादमी घरोंडा (करनाल) में खोलने की मंजूरी।
- बहादुरगढ़ में पीडीएम विश्वविद्यालय स्थापित तथा गुड़गांव में स्टार एक्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिल पास।
- स्टार्ट-अप कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया।
- डॉ. मंगलसेन जी के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध करने तथा उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में एक पीठ स्थापित।
- ANOs का विभिन्न कैम्पों के लिए मैसिंग अलाउंस 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
- एन.सी.सी. कैडेट्स का रिफ्रैशमेंट भत्ता 25 रुपये प्रति परेड किया।
- सभी विश्वविद्यालयों में 'दीनदयाल उपाध्याय' केन्द्र स्थापित करने का निर्णय।
- वर्ष 2015-16 के लिए राज्य को 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना' के अन्तर्गत 5 अवार्ड प्राप्त हुए।
- छात्राओं की स्नातक स्तर तक राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ट्यूशन फीस माफ।
- विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को अर्ध सरकारी पत्र जारी किया गया।
- छात्र संघ के चुनाव पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया, जिसके लिए एक कमेटी गठित।
- एन.सी.सी. की तर्ज पर हरियाणा कैडेट्स कोर की स्कूलों, कॉलेजों में शीघ्र शुरूआत।

डॉ. मंगलसेन जी के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में एक पीठ स्थापित।

तकनीकी शिक्षा -स्वर्णिम भविष्य का प्रतीक

- 12वीं के समकक्ष प्रदेश में बहुतकनीकी डिप्लोमा कोर्स की शुरूआत। अब स्नातक में प्रवेश पात्र की प्रक्रिया शुरू ।
- गांव दुधोला (पलवल) में कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू ।
- युवाओं को आर्थिक तथा चहुंमुखी विकास में भागीदार बनाने के लिए 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' के तहत युवाओं को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
- केन्द्र सरकार की 'एकीकृत कौशल विकास योजना' के तहत 20,000 लोगों को प्रशिक्षण।
- अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत और फरीदाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत, जिनमें 3500 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा तथा 4000 से ज्यादा छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने हेतु समझौता।
- राजकीय बहुतकनीकी, नीमका (फरीदाबाद) में एम.एस.एम.बी. का केन्द्र खुलेगा।

गांव दुधोला (पलवल) में स्थापित होगा कौशल विकास विश्वविद्यालय

- पांच नये बहुतकनीकी इंद्री (मेवात), मालब (मेवात), छप्पार (भिवानी), जमालपुर शेखां (फतेहाबाद) तथा मन्डकोला (पलवल) निर्माणाधीन।
- राजकीय बहुतकनीकी एवं 'बहु कौशल विकास केन्द्र' पंचकूला और गांव धामलावास (रेवाड़ी) में स्थापित करने का निर्णय।
- दो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, चीका (कैथल) व लिसाणा (रेवाड़ी) में स्थापित, 4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-हथनी कुंड (यमुनानगर), उमरी (कुरुक्षेत्र), जाट्टल (पानीपत) तथा धांगड़ (फतेहाबाद) का निर्माण कार्य पूर्ण तथा राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर (पचंकूला) का कार्य निर्माणाधीन।
- कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।
- करनाल में केन्द्रीय प्लास्टिक सैटेलाइट केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।
- पंचकूला में 10.45 एकड़ भूमि पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- उमरी (कुरुक्षेत्र) में राष्ट्रीय डिजाईन सस्थान (एन. आई डी.) की स्थापना की जा रही है।
- ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम के तहत 990 सरकारी स्कूलों में 14 व्यवसायिक ट्रेड्स शुरू।

बहुतकनीकी डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष

औद्योगिक प्रशिक्षण से युवाओं का कौशल विकास

- प्रदेश में 18 नये राजकीय तथा 110 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू।
- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहली बार ऑनलाइन दाखिला शुरू।
- औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग प्रदेश का पहला पेपरलैस विभाग।
- राज्य के 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 15 नये व्यवसाय कोर्स शुरू, जिनमें 324 नईं ट्रेड यूनिटें तथा 9984 अतिरिक्त सीटें जारी।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण हुए 11, 261 विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहली बार ऑनलाइन दाखिला

Launc
of
CM's e-Dash
(Key Performance
4th December, 2

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति

- 'शासन कम से कम-सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्त के मद्देनज़र आई.टी. का अधिक से अधिक प्रयोग करके भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
- प्रदेश में 125 ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से 117 ई-सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- प्रदेश में 4435 सांझा सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई, जिनमें से 3160 सांझा सेवा केन्द्रों पर सेवाएं शुरू।
- आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला देश का अग्रणी राज्य, जिसके तहत जन्म से 5 साल तक के बच्चों का आधार सक्षम पंजीकरण शुरू।
- नागरिकों की समस्याओं तथा शिकायतों के जल्द निवारण के लिए 'सी.एम.विन्डो' के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से सीधा सम्पर्क किया जा रहा है। 10 अक्तूबर, 2016 तक 2,08,414 शिकायतें, मांग और सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 1,67,578 शिकायतों का समाधान हुआ।
- ई-शासन प्रणाली के बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रदेश 'स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस' अवार्ड-2015 से सम्मानित।
- राज्य को प्रतिष्ठित अवार्ड 'एक्सिलेंस ऑफ सी.एस.आई.नीहिलेंट' अवार्ड से नवाजा गया।
- सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के अन्तर्गत 195 सेवाएं अधिसूचित। एक हजार रुपये से अधिक सभी अदायगियां केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगी।

125 ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से 117 ई-सेवाएं

2 साल सबका ख़्याल

- प्रदेश में स्थापित 375 स्थाई नामांकन केन्द्रों के माध्यम से आधार कार्ड बनाने के 100 प्रतिशत लक्ष्य के एवज में 99.38 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
- ई-साक्षर बनाने के उद्देश्य से 'नेशनल डिजिटल साक्षरता परियोजना' के तहत 1,48,203 नागरिकों का पंजीकरण।
- कनैक्टिविटी बढ़ाने के लिए सभी गांवों को मार्च, 2017 तक ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा, अब तक 3801 गांव जुड़े।
- सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करने के लिए जिला गुरुग्राम, बावल तहसील, धारुहेड़ा सब-तहसील, जिला पंचकूला बरवाला ब्लॉक व दूसरे (इंडस्ट्रियल एरिया-।। शामिल), फरीदाबाद व पलवल जिलों को अम्बाला व यमुनानगर, कुण्डली-राई मॉडल इन्डस्ट्रियल टाऊन तथा झज्जर के एरिया को 'ब्राउन फील्ड एरियाज़' के रूप में अधिसूचित करवाया।
- प्रदेश के स्टेट वैब पोर्टल से सभी विभागों/बोर्डों इत्यादि की वैबसाइट को लिंक किया।
- मुख्यमंत्री 'डैश बोर्ड' की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के 200 से अधिक मापदण्डों के उच्चतम स्तर पर निगरानी करके जन साधारण को प्रभावी तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने तथा कल्याणकारी नीतियों में जन-भागीदारी बढ़ाने के लिए www.haryanacmoffice.gov.in नामक सी.एम. वेबपोर्टल शुरू।
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम क्षेत्र के 25 पाठ्यक्रमों में हार्डवेयर दक्षता की नई योजना शुरू।
- मुरथल (सोनीपत) में 191 करोड़ रुपये की लागत से एक साईंस सिटी तथा अंबाला में 5 एकड़ जमीन पर सब-रीजनल साईंस सैंटर स्थापित करने का निर्णय।

प्रदेश के स्टेट वैब पोर्टल से सभी विभागों/बोर्डों इत्यादि की वैबसाइट को लिंक किया ।

EESL
ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED
A JV of PSUs under the Ministry of Power
UJALA
UJALA

निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु प्रभावी कदम

- ''म्हारा गांव जगमग गांव'' योजना शुरू जिसके तहत 264 फीडर जिनमें लगभग 1000 गांव शामिल हैं, में बिजली सप्लाई 15 घंटे तक बढ़ाई गई है तथा अन्य 253 फीडर, जिनमें लगभग 900 से अधिक गांव हैं, को जल्द शामिल किया जाएगा।
- उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
- राज्य में 60 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की गई तथा 272 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई।
- प्रदेश में 617 किलोमीटर लम्बी नई लाईनें बिछाई गईं तथा 55,936 नये ट्रांसफार्मर लगाए गए।
- राज्य के सभी नागरिकों को सबसिडी दरों पर 60 लाख से अधिक एल.ई.डी.बल्ब दिए गये।
- प्रसारण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए आगामी 5 वर्षों (2021-22) के लिए 4452.97 करोड़ रुपये की योजना।
- वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 2149.38 करोड़ रुपये खर्च तथा आगामी 3 वर्षों के लिए 7359.30 करोड़ रुपये की योजना।
- कल्याणपुर-बादलपारा कोल ब्लॉक एच. पी. जी. सी. एल. को आवंटित करवाया गया।
- बिजली चोरी रोकने के लिए फीडर सैनीटेशन प्रोग्राम शुरू।
- स्वर्ण जयंती बिजली समिति डिस्कॉमज की प्रत्येक ऑपरेशन सब-डिविजन में गठित।
- कृषि की उत्पादन लागत को कम करने हेतु बिजली सबसिडी के लिए वर्ष 2016-17 में 6800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- गुरुग्राम में स्मार्ट इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने की परियोजना शुरू करने का निर्णय।
- 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत 316 करोड़ रुपये स्वीकृत।

उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार

- 'हरियाणा ग्लोबल सम्मिट-2016' में हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी-2016 का उद्घाटन, जिसमें 42 निवेशकों ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 93 करोड़ रुपये के निवेश के लिये सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए।
- गुरुग्राम में 121 देशों के संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस के वैश्विक सचिवालय का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- स्वर्ण जयन्ती वर्ष में एक लाख सौर प्रकाश प्रणालियां (मनोहर ज्योति) नामक नई परियोजना लागू, जिसके लिए 23.65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता स्वीकृत।
- छतों के ऊपर 'सौलर पावर प्लांट' लगाने के लिए हरियाणा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
- विभिन्न जिलों में 441.06 लाख रुपये की लागत से 69 ऑफ ग्रिड सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित।
- राज्य के 11 जिलों के 22 अनुसूचित जाति के गांवों में 4.80 करोड़ रुपये की लागत से 160 किलोवाट क्षमता की 1120 सौर पथ प्रकाश प्रणालियां लगाई।
- उद्योगों में बायोमास सह-उत्पादन से विद्युत पैदा करने के लिए करनाल, अम्बाला एवं पलवल में 16.60 मैगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं 73.46 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित।

गुरुग्राम में अन्तर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस वैश्विक सचिवालय निर्माणाधीन

- राज्य में 100 किलोवाट सम्बंद्ध भार या 120 के. वी. अनुबंध मांग से अधिक क्षमता की विभिन्न श्रेणियों की व्यवसायिक ईमारतों में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अनिवार्य किया।
- राज्य में 225.12 लाख रुपये की लागत से कुल 5682 सौर घरेलू प्रकाश प्रणालियां स्थापित।
- राज्य में 115 लाख रुपये की लागत से 2300 एल.ई.डी. सौर घरेलू प्रकाश प्रणालियां स्थापित।
- राज्य में 1,24,000 एल. पी. डी. क्षमता की 42 घरेलू सौर जल तापन प्रणालियों पर 6 लाख 26 हजार रुपये का अनुदान।
- राज्य में 21 लाख रुपये की लागत से 700 डिश टाईप सौर कुकर लाभार्थियों को वितरित।
- ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी तथा अर्ध सरकारी क्षेत्रों में नए सोडियम वाष्प लैंप की खरीद पर प्रतिबन्ध।
- सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों के ऐसे बिजली उपभोक्ताओं, जिनका सम्बद्ध भार 30 किलोवाट या उससे ऊपर है, एल.ई.डी. लैंप, ट्यूब लाईट, ऊर्जा कुशल लाईटों का उपयोग अनिवार्य।
- पानीपत में 10 मैगावाट का सौलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है।
- प्रदेश में 500 मैगावाट क्षमता के सौलर पार्क स्थापित करने के लिए सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन।

राज्य में 115 लाख रुपये की लागत से 2300 एल.ई.डी. सौर घरेलू प्रकाश प्रणालियां स्थापित।

hunt or
be hunted

औद्योगिक विकास-मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार

- संतुलित उद्योग विकास करने के लिए 'उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015' लागू।
- इस नीति का लक्ष्य राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक करना, चार लाख से अधिक रोज़गार सृजित करना और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना है।
- उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए E-biz Portal शुरू।
- कुल 8003 सूक्ष्म व लघु उद्योग तथा 265 मध्यम व बड़े उद्योग स्थापित हुए जिनमें 16,571 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 1,59,703 लोगों को रोजगार मिला।
- निर्बाध, फाइन, विस्तार तथा प्रणेता इस नीति के प्रमुख स्तम्भ।
- 'हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड' गठित।
- राज्य में 74 नई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई गई।
- प्रदेश के 31 खण्डों में सी.एल.यू. और एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है और 75 खण्डों में सी.एल.यू. स्वतः ही हो जाएगा।
- राज्य में 10 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमोदनों/स्वीकृतियों तथा एक एकड़ से अधिक की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति 'हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड' द्वारा तथा 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी जा रही है।

एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए E-biz Portal

2 साल सबका ख़्याल

TOSHIBA
Deloitte.
ING

- अनुसूचित जाति के लोगों व महिलाओं को रोज़गार देने पर प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लोगों को रोज़गार देने पर प्रति वर्ष 30 हजार रुपये की रोज़गार सृजन सबसिडी पांच साल तक देने का प्रावधान।
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सैकेण्डरी सेक्टर के योगदान को 32 प्रतिशत किया।
- बॉयलर के निरीक्षण और पंजीकरण के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए ऑनलाइन सुविधा।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमकर्ता ज्ञापन फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा।
- उद्योगों को सभी प्रकार की आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 'उद्यम सहायता समूह' का गठन करने का निर्णय।
- थीम कलस्टर-पर्यटन, मनोरंजन, उद्योगों इत्यादि के लिए के. एम. पी. के साथ-साथ 'ग्लोबल इकॉनोमिक कॉरीडोर' की स्थापना का निर्णय।
- हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण विनियम एवं अधिनयम के तहत समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सैकेण्डरी सेक्टर के योगदान को 32 प्रतिशत किया।

2 साल
सबका ख़्याल

निवेश आकर्षित करने में अग्रणी हरियाणा

- गुरु ग्राम में आयोजित 'हैपनिंग हरियाणा' ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट बेहद सफल रही। वर्ष 2018 में इस सम्मिट का आयोजन पुनः किया जाएगा।
- इस सम्मिट में 12 भागीदार देशों अर्थात चीन, चेक गणराज्य, जापान, मॉरीशस, मलावी, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, स्पेन, टशूनीशिया, यू.के. और कनाडा के ओंटारिया प्रान्त ने भाग लिया।
- इस सम्मिट में कुल 359 एम.ओ.यू. हुए हैं, जिनके क्रियान्वित होने से प्रदेश में लगभग 584 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। सरकार की उपलब्धि सही मायनों में उम्मीदों से 5 गुणा अधिक है।
- राज्य में अब तक कुल 407 एम.ओ.यू. साईन हुए, जिनसे 6.41 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना।
- इन निवेशों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए Fast Track Clearance की व्यवस्था की गई।

407 एमओयू साईन होने से 641 लाख करोड़ रुपये के निवेश की सम्भावना

Happening HARYANA
GLOBAL INVESTORS SUMMIT
CII

- सम्मिट में वांडा ग्रुप ने डेढ़ से दो लाख रोज़गार के अवसरों के सृजन हेतु निवेश करने, जापान के राजदूत ने झज्जर में समेकित औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने, इंडिया और साउथ एशिया पैनासोनिक द्वारा झज्जर टैक्नो पार्क में लाई-आई.ओन स्टोरेज बैटरी प्लांट स्थापित करने तथा मेदांता ने एक मेडिकल स्कूल और 1000 बिस्तरों का अस्पताल खोलने की घोषणा की।
- प्रदेश में 9 फूड प्रोसैसिंग इकाइयां स्थापित, जिनके लिये 17 करोड़ 28 लाख रुपये का अनुदान।
- बरही, सोनीपत के 75 एकड़ क्षेत्र में 177 करोड़ रुपये के निवेश से मेगा फूड पार्क की स्थापना, जिससे 12 हजार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
- नारनौल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को मंजूरी।

प्रदेश में 9 फूड प्रोसैसिंग इकाइयां स्थापित, जिनके लिये 17 करोड़ 28 लाख रुपये का अनुदान।

Happening
HARYANA

हरियाणा विदेशी निवेशकों की पहली पंसद

- माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका व कनाडा दौरे के दौरान निवेशकों को प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया।
- इस दौरान यूनाइटेड टैक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, एलगोनक्वीन कॉलेज, अप्लाईड मैटिरियल, गूगल तथा सिस्को के साथ पांच महत्वपूर्ण समझौते हुए।
- कनेक्टिकट के गवर्नर डेनल पी. मैलोए द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों को सांझा करने के लिए दीर्घावधि भागीदारी की पेशकश की गई।
- मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री ब्यॉड के. रथरफोर्ड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी, जीव-विज्ञान एवं कृषि, साइबर सुरक्षा तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की गई।
- अमेरिका व कनाडा दौरे के परिणामस्वरूप प्रदेश में अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश तथा प्रदेश के 40 हजार लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना।
- जनवरी, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने चीन एवं जापान दौरे के दौरान बीजिंग (चीन) में सम्भावी निवेशकों के साथ आठ समझौते किये।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु हरियाणा सरकार तथा जापान के मिजुहों बैंक लिमिटेड के साथ टोकियो में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- ये समझौते वाण्डा, चाइना लैंड डेवलपमेंट कम्पनी प्राइवेट, लिमिटेड, जैड.टी.ई. कॉरपोरेशन आदि जैसी बड़ी कम्पनियों के साथ हुए। वाण्डा ग्रुप हरियाणा में कुल 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा।

विदेशी निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण समझौते

1008

खनन के ठेकों में पारदर्शिता

- खनन के ठेकों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ी खनन इकाइयों/ब्लॉकों को ठेके पर देने के बजाय छोटी खनन इकाइयों/ ब्लॉकों को खुली नीलामी की बजाय ई-नीलामी के द्वारा आवंटित किये गये, जिससे निर्माण सामग्री की कीमतों में कमी आएगी।
- रॉयल्टी एवं करों के संग्रहण को सरल बनाने और कर चोरी कम करने के लिए यमुनानगर में 'ई-रवाना' योजना शुरू, जिसे सभी जिलों में शुरू किया जाएगा।
- स्टोन क्रैशर स्थापित करने और स्क्रीनिंग प्लांट लगाने हेतु राहत देने की नई नीति बनाई।
- जिन बड़ी खनन इकाइयों के ठेके/पट्टे रद्द किए गए थे, उनमें से अब तक कुल 89 छोटे खनन खण्ड बनाकर ई-नीलामी की गई।
- गांव खानक (भिवानी) की पत्थर की खान का पट्टा एच.एस.आई.आई.डी.सी.को प्रदान किया गया है।

खनन के ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-नीलामी शुरू

सड़कों का विस्तार-विकास का आधार

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 135 किलोमीटर लम्बे छः लेन कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे, 136 किलोमीटर लम्बे कुण्डली गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे तथा दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक 70 किलोमीटर एन.एच.-1 को 8 लेन करने की आधारशिला रखी गई, जिन पर 13,802 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- दशकों से अधूरे पड़े कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पुनः शुरू तथा इस एक्सप्रेस-वे के 52.33 किलोमीटर खण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण करवा कर यातायात के लिए शुरू।
- राजमार्गों, जिला एवं ग्रामीण सड़कों के सुधार और मरम्मत के लिए 1560 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत।
- यातायात को सुगम बनाने के लिये 8 टोल टैक्स बैरियर हटाये।
- राज्य में 3531 करोड़ रुपये से 7230 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण व सुधार पर खर्च।
- प्रदेश में 437 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और 505 किलोमीटर लम्बे नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित।
- एन. सी. आर. में सड़क और पुलों के निर्माण कार्यों पर 158 करोड़ रुपये खर्च।

कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पुनः शुरू

2 साल सबका ख़्याल

पुलों का निर्माण-यातायात आसान

फरीदाबाद के सैक्टर 59-61 में 6 लेन रेलवे ऊपरिगामी पुलों का निर्माण

- दिल्ली-मथुरा रेलवे लाइन के नजदीक मैलरेना रेलवे क्रॉसिंग फरीदाबाद के सैक्टर 59-61 में 6 लेन रेलवे ऊपरिगामी पुलों का निर्माण कार्य पूरा।
- पुराने फरीदाबाद के नजदीक रेलवे अधोगामी पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-3, फरीदाबाद में दोहरे रास्ते का निर्माण किया गया।
- राज्य में 13 आर.ओ.बी, 11 आर.यू.बी.पर 558 करोड़ रुपये खर्च तथा 17 आर.ओ.बी.व 5 आर.यू.बी.का कार्य प्रगति पर।

2 साल सबका ख़्याल

EXIT
RAPID METRO

रेल यातायात को नई दिशा

- देश की पहली सी.एन.जी. आधारित डी.ई.एम.यू. रेल सेवा रेवाड़ी से रोहतक के बीच शुरू।
- राज्य में 740 करोड़ रुपये की लागत से 81 किलोमीटर लम्बी सोनीपत-जींद रेलवे लाइन जनता को समर्पित।
- फरुखनगर-चरखी दादरी वाया झज्जर-65 किलोमीटर तथा हिसार व नरवाना के बीच नई रेल लाइन-65 किलोमीटर का सर्वेक्षण कार्य शुरू।
- मथुरा-पलवल चौथी लाइन-80 किलोमीटर, बाईपास अम्बाला-मोहड़ी-शम्भू 7 किलोमीटर तथा रोहतक-भिवानी 48 किलोमीटर के लिए 1074 करोड़ रुपये की तीन नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति।
- हरियाणा 'मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' का गठन।

राज्य में 740 करोड़ रुपये की लागत से 81 किलोमीटर लम्बी सोनीपत-जींद रेलवे लाइन जनता को समर्पित।

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति-सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

- पानी व सीवरेज के कनैक्शन लेने व बिलों का भुगतान करने के लिए शिकायत निवारण केन्द्र पर ऑनलाइन सुविधा शुरू।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 7 शहरों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने व इनके सुधार हेतु 309 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रगति पर।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 116 नहर आधारित जलघर स्थापित।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 981 नलकूप तथा 249 बूस्टिंग स्टेशन शुरू।
- प्रदेश के 603 गांवों में पेयजल सुविधा में सुधार एवं बढ़ोतरी।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 4568 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें बिछाई गईं।
- राज्य के 33 शहरों में मल शोधन संयंत्र शुरू तथा 28 मल शोधन संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज़ सुविधाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 88 करोड़ रुपये तथा सीवरेज उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए 129 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 981 नलकूप तथा 249 बूस्टिंग स्टेशन शुरू

UMMIT - HAR
mber 2016, Red Bishop, Panc
& Taxation Department, Harya
Knowledge Partners
NDIA
GST
SUMMIT
HARYANA

कराधान के क्षेत्र में ई-सेवाओं की शुरुआत

- कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फायलिंग, ई-निविदा एवं सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू।
- व्यापारियों के लिए ई-रिफंड ऑनलाइन सुविधा शुरू।
- प्रदेश में जी.एस.टी. लागू करने के लिए अधिनियम पारित।
- ई-सेवाओं को लागू करके इंस्पैक्टर राज की दखलअदांजी को किया समाप्त।
- शराब के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए ई-परमिट एवं ई-पास प्रणाली शुरू।
- पांच सौ रुपये और इससे अधिक के एमआरपी. वाले जूतों पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर की 5 प्रतिशत।
- कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में निर्मित 'खल', 'बिनौला', 'बेसन' तथा 'सूती धागे' को कर से छूट।
- इलैक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर की 5 प्रतिशत।
- ग्राहकों को खरीदे गए माल का बिल या इनवायस लेने के लिए 'अपना बिल-अपना विकास' योजना होगी शुरू।
- हर जिले में सबसे अधिक कर अदा करने वाले 3 व्यक्तियों को सम्मानित करने की योजना।
- एल. ई. डी. लाईटों, पाइप फिटिंग एवं प्री. फेव स्टील स्ट्रक्चर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 की प्रतिशत ।
- आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित पंजीकृत डीलरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य देय राशि से राहत देने के लिए 'आम राहत' योजना बनाई।
- मेहंदी व बायो डीजल पर वैट समाप्त।
- कर अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें आर्थिक सतर्कता और जी.एस.टी. दो इकाइयां होंगी।

व्यापारियों के लिए ई-रिफंड ऑनलाइन सुविधा शुरू

MEDICAL
MEDICAL

सस्ती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं

- जन्म के समय कन्या लिंगानुपात 900 के पार-लगातार सुधार।
- प्रदेश के सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों में 570 आवश्यक दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं।
- प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने का लक्ष्य, जिसके तहत पंचकूला, भिवानी और जींद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू।
- हरियाणा को चिकित्सा शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कुटैल (करनाल) में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू।
- सरकारी अस्पतालों में ई-उपचार प्रबन्धन तथा सूचना प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसका पहला चरण नागरिक अस्पताल, सेक्टर-6 पंचकूला, सी. एच. सी. , रायपुररानी, पी. एच. सी. , बरवाला, बी. पी. एस. महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत) में पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 के अन्त तक सभी जिला अस्पतालों में शुरू करने का प्रस्ताव।
- परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों में गर्भनिरोधक टीके को सर्वप्रथम शामिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- राज्य के चार जिलों मेवात, पलवल, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी की सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं पर जनता के मुफ्त-उपयोग हेतु Pathfinder International के तकनीकी सहयोग से उपलब्ध करवाने के साथ अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

2 साल
सबका ख़्याल

- हरियाणा देश के चुनिंदा चार राज्यों में शामिल हो गया है, जहां टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोटा वायरस वैक्सिन की निःशुल्क शुरुआत की है।
- 'मिशन इन्द्रधनुष' के तहत वर्ष 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सम्पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित।
- राज्य के 10 अस्पतालों, 14 सी.एच.सी, 20 पी.एच स़ी.के भवनों का निर्माण और लगगग 30 भवनों की मरम्मत की गई।
- प्रदेश के 4 अस्पताल, 13 सी.एच.सी.व 2 पी.एच.सी.को अपग्रेड किया गया।
- प्रदेश के 2 अस्पतालों व 3 मेडिकल कॉलेज में एम.आर.आई. तथा 3 अस्पतालों व 3 मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू।
- प्रदेश के 4 अस्पतालों में कैथ लैब स्थापित की जा रही है।
- 'मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना' के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में द्वितीय स्तरीय सर्जरियां निःशुल्क की जा रही हैं।
- इसके तहत 73 निःशुल्क मूलभूत प्रयोगशाला जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और ई.सी.जी., मुफ्त रेफरल परिवहन इन्डोर उपचार सेवाओं और 21 विभिन्न प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ 231 विभिन्न प्रकार के ऑप्रेशन किये जा रहे हैं।
- शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 36 हो गई है, इसके लिए 'नेशनल सम्मिट फॉर बेस्ट प्रैक्टिसिस' में प्रदेश को अधिकतम शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रथम पुरस्कार देने का निर्णय।

प्रदेश के 4 अस्पताल, 13 सी.एच.सी.व 2 पी.एच.सी.को अपग्रेड किया गया।

Bio Chemistry
HAEMATOLOGY ANALYZER

- नागरिक अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एम. आर. आई. एवं सी. टी. स्कैन मशीनें उपलब्ध करवाकर रेडियो डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाया।
- पंचकूला, फरीदाबाद, भिवानी, गुरुग्राम, खानपुर मेडिकल कॉलेज तथा पी.जी.आई, रोहतक में सस्ते रेट पर सी. टी. स्कैन तथा एम. आर. आई. की सुविधा उपलब्ध।
- डेंगू निदान एवं रोकथाम के लिए सभी जिला नागरिक अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध।
- नागरिक अस्पताल, पंचकूला को 300 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया।
- नागरिक अस्पताल, पानीपत में लगभग 42 करोड़ रुपये की लागत से 200 बिस्तरों का परिसर बनाने का कार्य प्रगति पर।
- प्रदेश में तम्बाकू सामग्री उक्त गुटका और पान-मसाला पर प्रतिबन्ध।
- पी. एन. डी. टी. तथा एम. टी. पी. एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 350 एफ. आई. आर. दर्ज।
- आशाओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर किया 1000 रुपये।
- डेंगू निदान एवं रोकथाम के लिए सभी जिला नागरिक अस्पतालों में मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें

प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज

- कुटैल (करनाल) में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू।
- हरियाणा को चिकित्सा शिक्षा हब के रूप में स्थापित करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है, जिसके तहत जिला पंचकूला, भिवानी और जींद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू।
- बाढ़सा (झज्जर) में 710 बिस्तरों के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शिलान्यास।
- पी. जी. आई, रोहतक में 'मरीज मित्र' योजना पायलट आधार पर शुरू, जिसका सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तक विस्तार करने की योजना।
- शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ में टीबी.के प्रति मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए एक सी.बी.एन.ए.ए.टी. मशीन स्थापित।
- भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां में डायलेसिस मशीन और केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित।

कुटैल (करनाल) में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू

2 साल सबका ख़्याल

गृह-उप स्वास्थ्य केन्द्र, बाछौद
निम्न सेवायें मुफ्त उपलब्ध हैं।
24 घन्टे प्रसूति सेवायें।
आपात स्थिति में परिवहन सेवा
जच्चा - बच्चा के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण
जच्चा - बच्चा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी व दुलार
प्रसूति गृह-उप स्वास्थ्य केन्द्र, बाछौद

ई. एस. आई. अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण

- शाहाबाद मारकंडा (कुरुक्षेत्र) व चरखी दादरी (भिवानी) में बीमाकृतों एवं उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सा बीमा व्यवसायी प्रणाली (आई.एम.पी.सिस्टम) लागू किया गया।
- ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का वर्दी धुलाई भत्ता बढ़ाकर किया 1150 रुपये मासिक।
- बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बरसत रोड, पानीपत, झाड़ली (झज्जर) तथा महेन्द्रगढ़ में डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति।
- बरवाला (पंचकूला), साहा (अम्बाला) व खरखौदा (सोनीपत) में मोबाईल डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति।
- अम्बाला क्षेत्र के बीमाकृतों को द्वितीय स्तर की कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने के लिए दो निजी व चैरिटेबल अस्पताल इम्पैनल किए गए।
- बहादुरगढ़ (झज्जर) में 100 बिस्तरों का अस्पताल खोलने का निर्णय।
- प्रदेश के 10 ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों को 6 बिस्तरों का अस्पताल तथा 3 ई.एस.आई.डिस्पेंसरियों को 30 बिस्तरों के अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
- ई.एस.आई. योजना को फरीदाबाद जिले में पूरी तरह लागू कर दिया गया है।
- ई.एस.आई.डिस्पेंसरी, पचंकूला को 5 डॉक्टर डिस्पेंसरी में अपग्रेड करने की स्वीकृति।

बरवाला (पंचकूला), साहा (अम्बाला) व खरखौदा (सोनीपत) में मोबाईल डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति।

आयुर्वेद चिकित्सा को प्राथमिकता

- आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्थान के लिए कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
- अब तक 1000 गांवों में से 600 गांवों में योगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। इसके अगले चरण में प्रदेश के शेष गांवों में भी योगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- गांव पट्टीकरा (नारनौल) में बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल का कार्य लगभग पूर्ण।
- पंचकूला में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष प्रकोष्ठों का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय।
- श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी भवन एवं ड्रग टैस्टिंग लैबोरेट्री का निर्माण कार्य पूर्ण।
- अम्बाला, भिवानी, गुरु ग्राम, हिसार, जीन्द, झज्जर, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत एवं यमुनानगर में पंचकर्मा केन्द्रों पर पंचकर्मा की सुविधा शुरू।
- फरीदाबाद एवं मेवात के पंचकर्मा केन्द्रों को पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है तथा फतेहाबाद, कैथल, करनाल एवं कुरुक्षेत्र में पंचकर्मा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।
- प्रदेश में पिछले दो वर्षों से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया गया तथा जिला व ब्लॉक स्तर पर भी योग दिवस समारोह आयोजित किये गये।

600 गांवों में योगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू

10101
01001
11010
10101
01001
11010

शहरों का कायाकल्प

- फरीदाबाद व करनाल शहर 'स्मार्ट सिटी' के लिए चयनित, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाओं का होगा विकास। प्रदेश सरकार गुरुग्राम को अपने संसाधनों से 'स्मार्ट सिटी' के रूप में कर रही है विकसित।
- हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 लागू जिसके अन्तर्गत पहली बार फ्लोर एरिया में 5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने का प्रावधान।
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने आवंटियों को बेहतर बुनियादी ढ़ांचे व अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 3238 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किये।
- 'अटल मिशन' योजना (अमृत) के अंतर्गत प्रदेश के 18 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया। वर्ष 2016-17 के बजट में 440 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सी.एल.यू. को ओर अधिक पारदर्शी, बाधारहित व समयबद्ध करने के लिए नये नीति निर्देश जारी।
- नगर निकायों को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 3452 करोड़ 96 लाख रुपये दिये गये।
- शहरी विकास मिशन के तहत 1323.54 करोड़ रुपये नगर पालिकाओं को दिये गये।
- करनाल तथा जींद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल।

फरीदाबाद, करनाल व गुरुग्राम शहर होंगे 'स्मार्ट सिटी'

2 साल सबका ख़्याल

CASIO

- नगर परिषद्, सोनीपत को नगर निगम तथा बराड़ा व रादौर कस्बे को नगर पालिका का दर्जा दिया गया।
- नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पालिका के सम्पत्ति मालिकों को 30 प्रतिशत एकमुश्त छूट प्रदान, जिन्होंने वर्ष 2010-11 व 2012-13 के अपने सभी बकाया चुका दिये हों।
- आरक्षण आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई रिहायशी, वाणिज्यिक व संस्थागत सम्पत्तियों को एक वर्ष (1.4.2016 से 31.3.2017) की अवधि के लिए सम्पत्ति कर से छूट।
- राज्य की चार पालिकाओं को छोड़कर शेष सभी पालिकाओं में इलैक्ट्रॉनिक टैंडरिंग व्यवस्था शुरू।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का शुभारम्भ, जिसके तहत राज्य के सभी जिले कवर किये जायेंगे।
- 'स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत' अभियान के तहत शहरों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 1400 रुपये की वित्तीय सहायता।
- 'स्वच्छता शहरी पुरस्कार योजना' के तहत सबसे अच्छे वार्ड को क्रमशः दो लाख रुपये, एक लाख रुपये व 50 हजार रुपये के पुरस्कार दिये जायेंगे।

राज्य की चार पालिकाओं को छोड़कर शेष सभी पालिकाओं में इलैक्ट्रॉनिक टैंडरिंग व्यवस्था शुरू।

निकास
Exit

मैट्रो से बदलेगी हरियाणा की तस्वीर

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 13.87 किलोमीटर लम्बी बदरपुर-मुजेसर मैट्रो रेल सेवा का शुभारम्भ।
- मैट्रो परियोजनाओं के लिए लगभग 707 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।
- फरीदाबाद के वाई. एम. सी. ए. चौक से बल्लभगढ़ तक मैट्रो विस्तार का कार्य शुरू।
- मैट्रो का बहादुरगढ़ तक विस्तार करने का कार्य प्रगति पर।
- गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से सोहना रोड तक तथा सोनीपत के कुण्डली तक मैट्रो के विस्तार की योजना।
- ट्राई सिटी में मैट्रो परियोजना के लिए यू. टी. प्रशासन, हरियाणा सरकार व पंजाब सरकार के बीच समझौता।

बदरपुर-मुजेसर मैट्रो रेल सेवा शुरू

2 साल
सबका ख़्याल

HMM
ASHOK LEYLAND
HMM

आधुनिक तथा सुगम परिवहन सेवाएं

- राज्य परिवहन की शहरी बस सेवा में तथा बड़े बस स्टैंडों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य शुरू।
- चालक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू।
- छात्राओं के लिए 88 मार्गों पर महिला बस सेवा आरम्भ।
- चण्डीगढ़ से जयपुर के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू।
- वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा।
- आपातकाल के पीड़ितों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में पति-पत्नी दोनों को मुफ्त यात्रा सुविधा तथा वोल्वो बसों के किराए में 75 प्रतिशत की छूट।
- इलेक्ट्रॉनिक मशीन से टिकट जारी करने, आर.एफ.आई.डी. पास देने तथा जी.पी.एस. प्रणाली शुरू की जायेगी।
- राज्य परिवहन बेड़े में 600 नई बसें शामिल करने की स्वीकृति।
- राज्य परिवहन के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता गर्मियों के लिए 1350 रुपये प्रतिवर्ष तथा सर्दियों के लिए 1450 रुपये प्रति तीन वर्ष किया।
- बस बेड़े में 484 नई बसें शामिल की गईं।
- रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में 36 घंटे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- नई राज्य सड़क सुरक्षा नीति-2016 बनाई गई।
- परिवहन वाहनों के रोड़ टैक्स के भुगतान के लिए ई-पेमैंट की सुविधा शुरू।
- ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए चौथा चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गांव कालूवास (भिवानी) में स्थापित किया जा रहा है।
- मोटर वाहनों में सड़क पात्रता की जांच के लिए गांव कनहेली (रोहतक) में 14.40 करोड़ रुपये से निरीक्षण और परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
- टैक्सी सेवा देने वाली कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।

बसों तथा बस स्टैंडों पर सीसीटीवी. कैमरे लगाने का कार्य शुरू

हवाई अड्डों का अपग्रेडेशन

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा चण्डीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया।
- हिसार हवाई अडड्ा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अडड्ा बनाने की प्रक्रिया शुरू।
- कुरुक्षेत्र व करनाल के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा।

2 साल
सबका ख़्याल

सामाजिक सुरक्षा की नई पहल

- हरियाणा देश का प्रमुख राज्य, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है।
- सभी प्रकार की सामाजिक पेंशनों को पहली जनवरी, 2016 से बढ़ाकर 1400 रुपये प्रतिमास किया गया तथा इनमें प्रतिवर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है।
- सभी श्रेणी के दिव्यांग जैसे नेत्रहीन, मूक एवं बधिर व्यक्तियों को जिला स्तर पर कृत्रिम अंग मुफ्त प्रदान किये जाते हैं।
- प्रदेश के 1,03,183 'निराश्रित बच्चों को 500 रुपये प्रतिमास वित्तीय सहायता' दी जा रही है।
- 'कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता' योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से अधिकतम 5000 रुपये प्रति परिवार पांच वर्ष तक दिये जाते हैं।
- स्कूल न जाने वाले 18 वर्ष तक के शत-प्रतिशत निःशक्त बच्चों को 700 रुपये मासिक वित्तीय सहायता।
- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी व भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

शत-प्रतिशत पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजने वाला हरियाणा देश का प्रमुख राज्य

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान

अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

प्रधानमंत्री mudra योजना

स्वस्थ धरा, खेत हरा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

नागरिकों की सुरक्षा हेतु योजनाएं

- सभी नागरिकों को बैंक खाते से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े हर परिवार का जीरो बैलेंस पर एक लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर के साथ खाता खोला गया। अब तक 53 लाख 42 हजार 632 बैंक खाते खोले गये।
- 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा' योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक के सभी बचत बैंक खाताधारकों का मात्र 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु जोखिम कवर बीमा किया जा रहा है। अब तक 24 लाख 11 हजार 896 लोगों का पंजीकरण किया गया।
- 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत उपभोक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा' योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु तक के सभी बचत बैंक खाताधारकों का 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा किया जा रहा है। अब तक 7,83,404 लोगों का पंजीकरण किया गया।
- वृद्धावस्था में आय सुनिश्चित करने व असंगठित क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'अटल पेंशन' योजना शुरू, जिसके अन्तर्गत 1000 रुपये से 5000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन की गारंटी सुनिश्चित तथा 73,530 लोगों का पंजीकरण किया गया।
- प्रत्येक बैंक शाखा से ऋण लेने वाले कम से कम एक अनुसूचित जाति व जनजाति तथा कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 'स्टैंड-अप इंडिया स्कीम' शुरू।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत उपभोक्ताओं को 10 लाख रुपये तक का सस्ता ऋण

पास बुक
PASS BOOK
सुकन्या समृद्धि खाता
SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT
H.O PANIPAT
PAWNI
3

बेटी को सलाम–राष्ट्र के नाम

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये पानीपत से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम शुरू किया गया, जो मेवात को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुरू।
- 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा रहा है। इस अल्प बचत योजना पर ब्याज की दर सबसे अधिक है।
- महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए 'हरियाणा कन्या कोष' स्थापित।
- प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से अधिक हो गया है, जिसके लिए हरियाणा को 'नारी शक्ति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया। हरियाणा में लिंगानुपात की दर 950 तक करने का सरकार का लक्ष्य है।
- 'आपकी बेटी -हमारी बेटी' योजना के तहत अब तीसरी बेटी के जन्म पर भी 21,000 रुपये की राशि दी जाती है।
- लिंगानुपात में सुधार के लिए नारनौल, भिवानी और झज्जर जिले सम्मानित।

'हरियाणा कन्या कोष' स्थापित

सशक्त महिला-सशक्त समाज

- हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल में वन स्टॉप सैंटर 'सखी' स्थापित तथा रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार व नारनौल में भी किये जायेंगे स्थापित।
- देश का पहला 'नन्दघर' नामक अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केन्द्र गांव हसनपुर (सोनीपत) में शुरू।
- पंचकूला, जींद, नारनौल और मेवात जिले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण सुधार के लिए 'जिला स्तरीय पोषण पुरस्कार' से सम्मानित।
- 'ग्रामीण किशोरी बालिका को पुरस्कार योजना' के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर तीन बालिकाओं को क्रमशः 8,000 रुपये, 6,000 रुपये तथा 4,000 रुपये की राशि के पुरस्कार।
- बारहवीं परीक्षा में खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर तीन बालिकाओं को क्रमशः 12,000 रुपये, 10,000 रुपये और 8,000 रुपये की राशि के पुरस्कार।
- महिलाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से एक समझौता किया गया है, जिसके तहत आगामी दो वर्षों में प्रदेश की 10 हजार महिलाओं का दक्षता विकास किया जाएगा।

देश का पहला 'नन्दघर' नामक अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केन्द्र गांव हसनपुर (सोनीपत) में शुरू

2 साल
सबका ख़्याल

- गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ऑप्रेशन 'मुस्कान' के तहत राज्य में 5366 गुमशुदा बच्चों की पहचान करके 4015 बच्चों को उनके मां-बाप व संरक्षकों को सौंपा गया।
- ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता के पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 2100 रुपये, 1100 रुपये व 750 रुपये की।
- जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर क्रमशः 4100 रुपये, 3100 रुपये व 2100 रुपये की।
- राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर क्रमशः 11,000 रुपये, 8,100 रुपये व 4,100 रुपये की।
- 'सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार योजना' के तहत सर्कल स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर क्रमशः 2000 रुपये, 1200 रुपये व 800 रुपये तथा ब्लॉक स्तर पर क्रमशः 4000 रुपये, 3000 रुपये व 2000 रुपये की।
- बालिकाओं के संरक्षण और समाज में उनको उचित हक दिलाने के उद्देश्य से 'बेटी बचाओ आशा प्रोत्साहन' योजना शुरू।
- राष्ट्रीय मिशन की संशोधित ग्राम अभिसरण एवं सुविधा सेवा योजना के अन्तर्गत फरीदाबाद व गुरुग्राम जिले शामिल।

हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए करनाल में वन स्टॉप सैंटर 'सखी' स्थापित

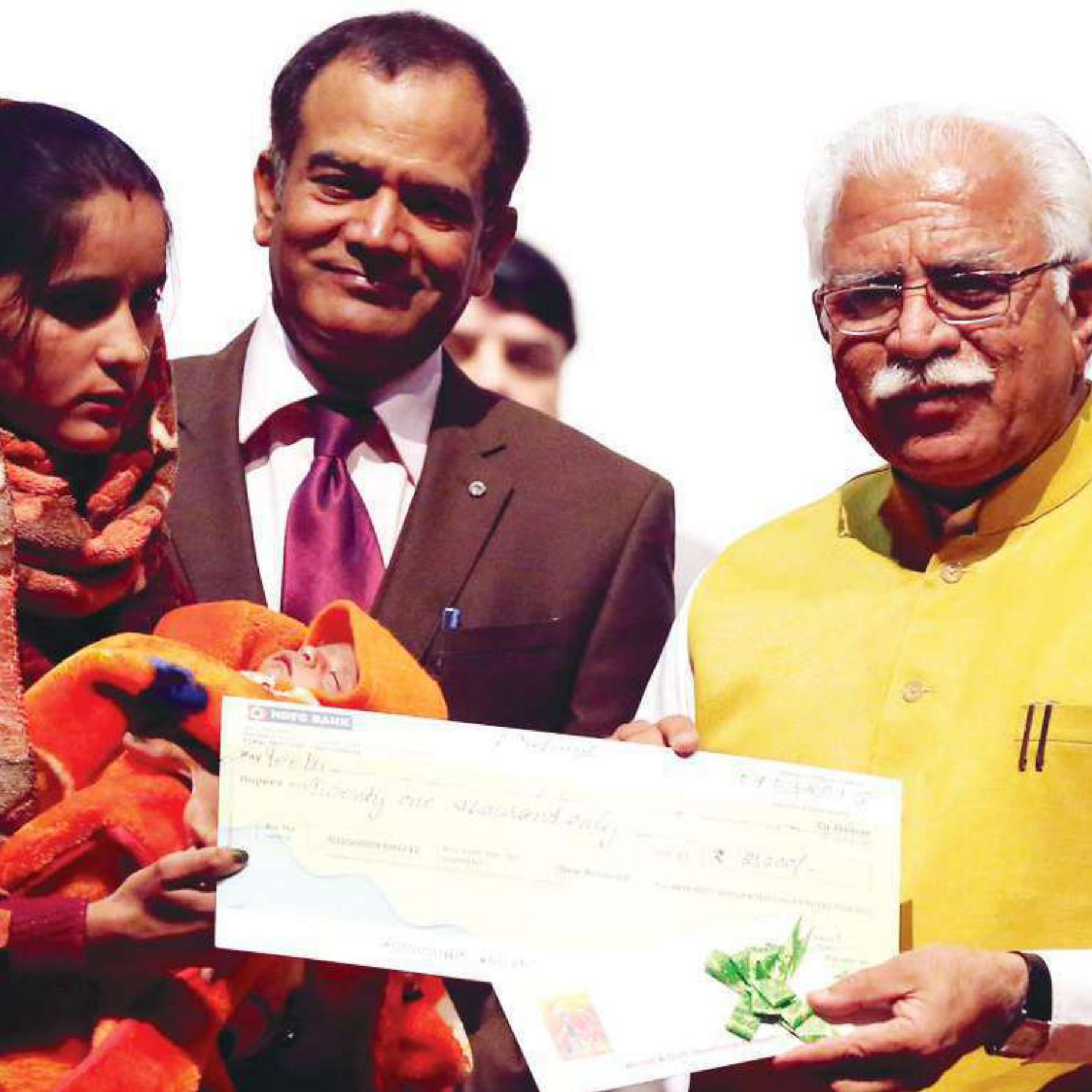
HDFC BANK

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा

- 'अन्तोदय -अन्तिम पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान' के सिद्धान्त के अनुरूप अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत बीपीएल.परिवारों की सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी पर 51,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को 41,000 रुपये की शगुन राशि दी जाती है।
- 'मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करने पर 1,01,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
- सभी वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा व निराश्रित महिलाएं तथा अनाथ व बेसहारा बच्चों की शादी के लिए 41,000 रुपये की राशि का प्रावधान जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम हो)।
- सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 11,000 रुपये की राशि का प्रावधान।
- किसी भी जाति एवं आय वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी को उसकी स्वयं की शादी के लिए 31,000 रुपये की राशि का प्रावधान।
- समाज के सभी वर्गों के लोगों, जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम भूमि या 1.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय हो, को उनकी लड़की की शादी के लिए 11,000 रुपये की राशि का प्रावधान।
- 'डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना' के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु मैट्रिकोत्तर स्तर तक कक्षावार 4000 रुपये से 12,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति।

'अन्तोदय -अन्तिम पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान' के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं

- वर्ष 2016-17 में 674.02 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जोकि वर्ष 2015-16 के दौरान आवंटित 366. 72 करोड़ रुपये के बजट से 83 प्रतिशत अधिक है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिमास 230 रुपये से 1200 रुपये तक छात्रवृत्ति तथा सभी नॉन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिमास 160 रुपये से 750 रुपये छात्रवृत्ति।
- 'अपग्रेडेशन ऑफ मैरिट ऑफ एस. सी. स्टूडेन्टस योजना' के अन्तर्गत छात्रावास में रहने वाले नौंवीं से बारहवीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करके प्रतियोगिता हेतु तैयारी करवाई जाती है।
- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपये की राशि का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अदालती मुकद्दमों की पैरवी को सुगम बनाने व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अन्तर्गत 85,000 रुपये से 825 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न उच्च प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति।
- गढ़ी लोहार जाति को टपरीवास जाति की सूची में शामिल किया गया, ताकि उन्हें भी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके।

हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति।

रियो ओलंपिक - 2016
Rio2016
कांस्य पदक विजेता
साक्षी मलिक
को ₹ 2.5 करोड़

गांवों में भी मिलेंगी भरपूर खेल सुविधाएं

- रियो ओलम्पिक में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी साक्षी मलिक को 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।
- रियो पैरालिम्पिक, एथलेटिक इवेंट में रजत पदक विजेता खिलाड़ी दीपा मलिक को 4 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय।
- रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, अमित कुमार तथा विरेन्द्र सिंह को अर्जुन पुरस्कार तथा कुश्ती प्रशिक्षक महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्ता नीति-2015 बनाई गई।
- अंतरराष्ट्रीय पहलवान गीता फौगाट को डीएसपी. तथा एवरेस्ट फतह करने वाले रामलाल को इंस्पैक्टर बनाने की मंजूरी।
- अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को 'हरियाणा राज्य डेवेल्पमैंट फंड' के तहत लगभग 92.40 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।
- खेलों के विस्तार के लिए खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- स्पोर्टस काउंसिल एक्ट को मंजूरी। अब स्टेट, जिला व ब्लॉक स्तर पर भी बनेंगी स्पोर्टस काउंसिल।
- प्रत्येक जिले में एक-एक खेल का 'स्वर्ण जयंती सैंटर ऑफ एक्सीलैंस' 5-5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में विभिन्न खेलों के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से स्वर्ण जयंती इण्डोर स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे।

साक्षी मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित

- प्रत्येक जिले में तीन करोड़ रुपये की लागत से 'स्वर्ण जयंती खेल सुविधा केन्द्र' की स्थापना की जायेगी।
- भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर हर वर्ष 23 मार्च को भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जायेगा।
- ओलम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपये देने का प्रावधान।
- एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 1.50 करोड़ रुपये, कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपये के नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.50 लाख रुपये देने का प्रावधान।
- कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को 1.50 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपये, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.50 लाख रुपये देने का प्रावधान।
- मोरनी में युवा साहसिक अकादमी की स्थापना की जा रही है।
- हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्ता प्राधिकरण गठित।
- हरियाणा के मान्यता प्राप्त खेल संघों को खेलों के विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य करने /योगदान के लिए 5 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान।
- राज्य में कुल 420 गोल्डन जुबली खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही है, जिनमें प्रत्येक जिले में 20 खेल नर्सरियां (10 लड़कों व 10 लड़कियों के लिए) स्थापित की जा रही हैं।

मोरनी में युवा साहसिक अकादमी की स्थापना की जा रही है।

पर्यटन को बढ़ावा

- 'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत कुरुक्षेत्र के पांच प्रमुख स्थल चिन्हित, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा 97.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।
- राज्य के तीर्थयात्रियों अधिकतम (50 यात्रियों तक) के लिए 'स्वर्ण जयन्ती गुरु दर्शन यात्रा' योजना शुरू, जिसमें श्री हजूर साहिब (नान्देड़), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंट साहिब तथा श्री पटना साहिब यात्रा शामिल हैं।
- स्वर्ण जयन्ती सिन्धु दर्शन योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री अधिकतम (50 यात्रियों तक) तथा मानसरोवर यात्रा योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति तीर्थ यात्री अधिकतम (50 यात्रियों तक) वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान।
- इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय 'सूरजकुण्ड हस्त मेले' में 23 देशों ने भाग लिया और 10 लाख से अधिक पर्यटक आये।
- हरियाणा केवल एक ऐसा राज्य है जहां होटल प्रबन्धन से संबंधित पांच संस्थान कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर व फरीदाबाद में कार्यरत हैं।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा ट्रैवल गाइड' नामक पुस्तक प्रकाशित।
- नारनौल-महेन्द्रगढ़-माधवगढ़-रेवाड़ी को ग्रामीण पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 80.79 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र को हरियाणा टूरिज्म का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया।

पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयन्ती उत्सव का आयोजन

सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु उचित कदम

- सरस्वती नदी के अनुसंधान एवं पुनरूत्थान के लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया गया तथा गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया।
- यमुनानगर के गांव मुगलवाली में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू, इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- पंचकूला में राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय तथा गांव राखीगढ़ी, जिला हिसार में स्थल संग्रहालय और व्याख्यान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
- संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए खण्ड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मुगलवाली गांव को बनाया जायेगा अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल

2 साल सबका ख़्याल

वीरों एवं शहीदों का बढ़ाया सम्मान

- युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की अनुग्रह राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा पुनः बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई।
- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में एन. एच. -1 पर अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक स्थापित किया जा रहा है।
- स्वतंत्रता सेनानियों व आई.एन.ए. के सदस्यों की प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को भी राष्ट्रीय एवं राजकीय पर्वों पर आमंत्रित किया जाएगा तथा स्वतंत्रता सेनानियों की भांति उनकी विधवाओं की अंत्येष्टि भी राजकीय सम्मान से की जाएगी।
- युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि निःशक्तता के आधार पर 5 लाख,10 लाख और 15 लाख रुपये की गई।
- सेना में कमीशन पाने वाले राज्य के अधिकारियों को कुशल प्रशिक्षण के उपरांत एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- सेना मेडल डिसटिंगविस्ड सर्विस/डिवोशन टू ड्यूटी के अवार्डी, जो कि फोर्सिज के हों और जिन्हें यह अवार्ड 31 मार्च, 2008 व 19 फरवरी, 2014 से पहले प्राप्त हुआ हो, को 34,000 रुपये नकद व 3,500 रुपये एन्यूटी दी जाती है तथा जिन्हें यह अवार्ड 19 फरवरी, 2014 के बाद मिला है, उन्हें 1.75 लाख रुपये की एकमुश्त नकद राशि दी जाती है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर 4,500 रुपये मासिक की गई।
- आपातकाल के दौरान पीड़ितों को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया।

युद्ध में शहीद वीर सैनिकों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

कर्मचारी कल्याण

- प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुरू।
- सफाई कर्मियों के सामने आने वाली दिक्कतों का निदान करने के लिए 'हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग' गठित करने की घोषणा।
- दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का मकान भत्ता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया।
- सेवा अवधि के दौरान एडहॉक, अनुबंध व डी.सी. रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तीन लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान।
- महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के लिए अर्जित अवकाश की शर्त से छूट प्रदान की गई।
- एक्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचर्स की मृत्यु उपरान्त परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें शीघ्र लागू करने के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है क्योंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसलिए कुछ परिवर्तन अवश्य होगा।
- पारिवारिक पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए निःशक्तता के कारण आजीविका से वंचित लड़की को उसकी शादी के बाद पारिवारिक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पश्चात पैदा हुए पात्र निःशक्त बच्चे को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान।
- सरकारी कर्मचारियों को सभी प्रकार के ऋण बैंकों के माध्यम से देने का निर्णय।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुरू

सबके सिर पर छत

- प्रदेश में 119.57 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण तथा विभिन्न वर्गों के 13,115 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- आवास बोर्ड में ई-निविदा प्रणाली एवं निर्माणाधीन फ्लैटों की गुणवत्ता जांच हेतु तीसरी पार्टी निरीक्षण की प्रक्रिया आरम्भ।
- विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 882 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 11,259 ई.डब्ल्यू. एस. फ्लैट्स के निर्माण को मंजूरी।
- गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनने वाले फ्लैट्स के निर्माण कार्यों पर 436.90 करोड़ रुपये खर्च।
- पंचकूला में सैनिक व अर्धसैनिक बलों के लिए बनने वाले 279 टाईप-'ए' व 234 टाईप-'बी' फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- 'मिशन सभी के लिए घर-2022' के तहत शहरी गरीबों के आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 65 प्रतिशत रियायत।
- प्रदेश के छोटे व मध्यम शहरों में गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाने के लिए 'दीनदयाल जन आवास' योजना शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत अब तक 174 प्राइवेट कोलोनाईजर ने सस्ते आवास बनाने के लिए आवेदन पत्र जमा करवाये हैं।

शहरों में गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाने के लिए 'दीनदयाल जन आवास' योजना शुरू

हर घर हरियाली

- 'हर घर हरियाली' योजना के तहत प्रत्येक घर को हरा-भरा बनाने हेतु कलमी फलदार पौधों का पौधारोपण।
- गिद्ध सरंक्षण एवं संवर्धन केन्द्र, पिंजौर से गिद्धों को पहली बार उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।
- चालू वित्त वर्ष में राज्य में 2.07 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य। अब तक 1.77 करोड़ पौधों का पौधारोपण।
- मोरनी क्षेत्र में हर्बल फोरेस्ट नामक औषधीय उद्यान बनाने की प्रक्रिया शुरू।
- स्थानीय लोगों को वन एवं पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जोड़ने हेतु राज्य में 2200 स्वयं सहायता समूहों एवं 2487 ग्राम वन समितियों का गठन।
- पीपली के चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण पूर्ण तथा रोहतक चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण शुरू।
- जैविक स्त्रोतों के संरक्षण के लिए 'जैव विविधता बोर्ड' गठित।
- शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियों में जल एवं मृदा सरंक्षण हेतु जल संचय बांधों का निर्माण।
- खेती की जमीन को सेम से बचाने हेतु विशेष वृक्षारोपण।
- कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को आम लोगों के लिए खोला गया।
- ई-सर्विसिज़ के माध्यम से पेड़ों की कटाई हेतु अनुमति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

प्रत्येक घर को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

- सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद, जात-पात और क्षेत्रवाद को समाप्त करके भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाया।
- हरियाणा सिविल सर्विसिज की भर्ती का परिणाम साक्षात्कार के केवल 6 घंटे बाद घोषित।
- किसी भी सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- ''पुलिस भर्ती में पारदर्शिता'' (टी.आर प़ी.) पद्धति लागू की गई।
- पुलिस भर्ती में अर्ध सैनिक बलों के व्यक्तियों को भी मिलेगा मौका।
- विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू।

''पुलिस भर्ती में पारदर्शिता'' (टी.आर प़ी.) पद्धति लागू की गई।

2 साल
सबका ख़्याल

श्रमिकों का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान

- अकुशल श्रमिकों को 7976 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों को 10,180 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।
- कुशल श्रमिकों 'ए' को 9233. 44 रुपये तथा कुशल श्रमिकों 'बी' को 9695.12 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।
- मनरेगा के तहत 50 दिन तक कार्य करने वाले श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि वे कल्याण परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके।
- मनरेगा मजदूर जो भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं, की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है।
- भवन एवं सन्निमार्ण कल्याण बोर्ड में अपंजीकृत मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को 2. 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाती है।
- भवन एवं सन्निमार्ण कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को पहचान-पत्र के स्थान पर स्मार्ट कार्ड प्रदान करने का प्रावधान।
- श्रमिकों की पत्नियों को दी जाने वाली प्रसूति सहायता राशि को बढ़ाकर तीन लड़कियों तक, छात्रवृत्ति योजना का लाभ तीन लड़कियों व दो लड़कों तक तथा कन्यादान योजना का लाभ तीन लड़कियों की शादी तक किया।
- महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट।

मनरेगा मजदूर जो भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत

रोज़गार के नये अवसर

- बेरोज़गारी भत्ते की दरों का संशोधन किया गया। अब 12वीं पास युवाओं को 900 रुपये, स्नातक को 1500 रुपये तथा स्नातकोत्तर को 3000 रुपये मासिक भत्ता देने का निर्णय।
- स्नातकोत्तर स्तर के बेरोज़गार युवक, जो 100 घंटे काम करेंगे, उन्हें 9000 रुपये मासिक मानदेय देने का निर्णय।
- बेरोज़गार युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हिसार में राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र की स्थापना की गई।
- 1067 प्रार्थियों को रोज़गार उपलब्ध करवाया तथा 1797 प्रार्थियों को विदेशों में नौकरी के लिए पंजीकृत किया गया।

युवाओं को 100 घंटे काम करने पर 9000 रुपये मासिक मानदेय

प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था

- पुलिस में आई.टी. का प्रयोग करते हुए सिटीजन पोर्टल 'हरसमय' 24X7 स्थापित किया गया, जिससे लोग घर से ही शिकायत या एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकते हैं।
- एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जीरो एफ.आई.आर. की अवधारणा को अपनाते हुए प्रदेश के किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के पंजीकरण और जांच-पड़ताल की सुविधा के लिए हर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना व उपमण्डल स्तर पर महिला हैल्प-डेस्क स्थापित।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध की निगरानी करने के लिए हर जिले के महिला पुलिस थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।
- ऑप्रेशन संजय के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाए जा रहे हैं।
- कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ व आधुनिक बनाया जा रहा है।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तथा सुचारू यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस विभाग की सड़क सुरक्षा निधि स्वीकृत।
- विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हरियाणा पुलिस के 9 कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शौर्य सम्मान से पुरस्कृत।

पूरे प्रदेश में सीसीटीवी. कैमरे लगवाए जा रहे हैं

- अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (हरकोका) लागू किया जाएगा।
- फरवरी, 2016 में हुए आंदोलन के दौरान जिन असामाजिक ताकतों ने कानून को हाथ में लेकर लूटपाट और आगजनी जैसे अपराध किए, सरकार ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटी।
- राज्य में m-passport verification system आरम्भ किया जा रहा है इसकी पायलट टैस्टिंग के लिए जिला पंचकूला को चुना गया है।
- हरियाणा पुलिस को 3 सबसे अच्छे राज्यों में से उत्कृष्ट कार्य पासपोर्ट सत्यापन निश्चित समय में भेजने के लिए पुरस्कृत किया गया।
- भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने व उनके बारे में सूचना देने हेतु टोल फ्री चौकसी हेल्पलाइन नम्बर 1064 तथा टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022 शुरू।
- राज्य सतर्कता ब्यूरो ने जन साधारण को शिकायतें भेजने के लिए वट्सअप नम्बर 9417891064 उपलब्ध करवाया।
- राजस्व की चोरी रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 324 अपराधिक मुकद्दमें दर्ज।
- राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 218 नई जाचें दर्ज की गईं।
- सभी विभागों में मुख्य सर्तकता अधिकारी नियुक्त किए।

राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 218 नई जाचें दर्ज की गईं

हरियाणा की अर्थव्यवस्था देश में अग्रणी

- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा प्रदेश रैंकिग 'ईज़-ऑफ डूइंग बिजनेस' में चौदहवें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंची।
- 'स्वर्ण जयन्ती वित्त नीति संस्थान' स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वर्ष 2016-17 में प्रदेश के लिए कुल बजट 88,781.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
- वर्ष 2015-16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2015-16 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,65,204 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2014-15 में 1,50,260 रुपये थी।
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आंकलन करने के लिए श्वेत-पत्र जारी किये गये, ताकि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय किये जा सके।

वर्ष 2016-17 में प्रदेश के लिए कुल बजट 88,781.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

2 साल सबका ख़्याल